



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 12, 1994/फाल्गुन 21, 1915

No. 11]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 12, 1994/PHALGUNA 21, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य
क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक
नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other
than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1994

सा. का. नि. 128.—संविधान के अनुच्छेद 222
के खंड 2 के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्वारा निम्न आदेश
करते हैं यथा:—

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति
श्री भूपेन्द्र नाथ कृपाल जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से
स्थानान्तरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त गुजरात
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा की
अवधि के लिए 900 रुपये (केवल नौ सौ रुपये) प्रति माह
की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[सं. के. 13015/4/92—यू. एस. II (1)]

एस. के. बोस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(Department of Justice)

New Delhi, the 18th January, 1994

G.S.R. 128.—In pursuance of clause (2) of article 222 of
the Constitution, the President hereby makes the following
order namely:—

That Shri Justice Bhupinder Nath Kirpal, Chief Justice of
the Gujarat High Court, who has been transferred from the
Delhi High Court, shall be entitled to receive, in addition
to his salary, a compensatory allowance at the rate of
Rs 900 (Rupees nine hundred only) per mensem for the
period of his service as Chief Justice of the Gujarat High
Court

[No. K. 13015/4/92-US-II(i)]

S. K. BOSE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1994

सा. का. नि. 129.—संविधान के अनुच्छेद 222 के
खंड 2 के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्वारा निम्न आदेश करते
हैं यथा:—

ग्राम्प्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्याय-
मूर्ति श्री सुन्दरम नयनार सुन्दरम जिन्हें गुजरात उच्च

न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है अपने वेतन के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा की अवधि के लिए 900 रुपए (केवल नौ सौ रुपए) प्रति माह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[सं. के. 13015/4/92—यू. एस. II(ii)]
एस. के. बोस, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 18th January, 1994

G.S.R. 129.—In pursuance of clause (2) of article 222 of the Constitution, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Sundaram Nainar Sundaram, Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court, who has been transferred from the Gujarat High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a Compensatory Allowance at the rate of Rs. 900 (Rupees nine hundred only) per mensem for the period of his service as Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court.

[No. K. 13015/4/92-US-II(ii)]
S. K. BOSE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1994

सा. का. नि. 130.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड 2 के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्वारा निम्न आदेश करते हैं यथा:—

उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री गिरीश दाकोरलाल नानावटी जिन्हें गुजरात उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है अपने वेतन के अतिरिक्त उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा की अवधि के लिए 800 रुपए (केवल आठ सौ रुपए) प्रति माह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[सं. के. 13015/4/92-यू एस II (iii)]
एस. के. बोस, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 18th January, 1994

G.S.R. 130.—In pursuance of clause (2) of article 222 of the Constitution, the President hereby makes the following order, namely :—

That Shri Justice Girish Thakorlal Nanavati, Judge, Orissa High Court, who has been transferred from the Gujarat High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 800 (Rupees eight hundred only) per mensem for the period of his service as Judge, Orissa High Court.

[No. K. 13015/4/92-US-II(iii)]
S. K. BOSE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1994

सा. का. नि. 131.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड 2 के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्वारा निम्न आदेश करते हैं यथा:—

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री उल्लाल लक्ष्मीनारायण भट जिन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है अपने वेतन के अतिरिक्त मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा की अवधि के लिए 900 रुपए (केवल नौ सौ रुपए) प्रति माह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[सं. के. 13015/4/92-डेस्क-II (IV)]
एस. के. बोस, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 18th January, 1994

G.S.R. 131.—In pursuance of clause (2) of article 222 of the Constitution, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Ullal Lakshminarayana Bhat, Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court, who has been transferred from the Gauhati High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 900 (Rupees nine hundred only) per mensem for the period of his service as Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court.

[No. K. 13015/4/92-US-II(iv)]
S. K. BOSE, Jt. Secy.

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली 23 फरवरी, 1994

सा. का. नि. 132.—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (2) तथा (8) जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 25 और स्वापक औपधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36ग के साथ पढ़ा जाए, द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 सीमा-शुल्क अधिनियम 1962, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 कर्मचारी भविष्य - निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अधीन उत्पन्न होने वाले मुकदमों का संचालन करने के प्रयोजन के लिए तत्काल प्रभावी तिथि से श्री हारूभाई मेहना को वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक और श्री विवेक बागोट को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

निबंधन और शर्तें

1. यह नियुक्तियां तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।
2. इन नियुक्त व्यक्तियों को कोई रिटेनर अथवा मासिक पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।
3. श्री हारूभाई मेहता, वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक इस प्रकार के मामलों के प्रभारी होंगे। वे गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में इस आदेश के अनुसार नियुक्त किए गए श्री विवेक बारोट विशेष लोक अभियोजक को मामले चिन्हित (पार्क) करेंगे।

4. नियुक्त व्यक्ति निम्नलिखित शुल्क पाने के हकदार होंगे:—

- (क) शिकायत का प्रारूप 300/- रु. प्रति मुकदमा तैयार करने के लिए
- (ख) वास्तविक सुनवाई (i) 300/- रु. प्रति सत्र यथा पूर्वाह्न अथवा अपराह्न सत्र
- (II) 600/- रु. यदि पूर्वाह्न और अपराह्न दोनों सत्रों में वास्तविक सुनवाई होती है।
- (ग) वास्तविक सुनवाई:— 200/- रु. प्रति दिन ऐसी अधिकतम 5 सुनवाईयों तक
- (घ) सम्मेलन:— 60/- रु. प्रति घंटा अधिकतम 3 सम्मेलनों तक के लिए।

5. श्री हारूभाई मेहता, वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक और श्री विवेक बारोट, विशेष लोक अभियोजक उपर्युक्त संदर्भित किसी जी दांडिक मामले में भारत के संघ, अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के विरुद्ध गुजरात राज्य उच्च न्यायालय, अहमदाबाद में पेश नहीं होंगे।

6. यह नियुक्ति दोनों में से किसी भी एक पक्ष द्वारा लिखित रूप में एक माह का नोटिस देकर निरस्त की जा सकेगी।

[फा. सं. 36(10)/90-न्याय]

पी. सी. कण्णन, अपर विधि सलाहकार

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 23rd February, 1994

G.S.R. 132 :—In exercise of the powers conferred by Sub-Sections(2) & (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973, read with Section 25 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Section 36Cs of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance

Act, 1985, the Central Government hereby appoint with immediate effect Shri Haroobhai Mehta as Senior Special Public Prosecutor and Shri Vivek Barot, as Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases arising out of Central Excise and Salt Act, 1944, Customs Act, 1962, Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 in the Gujarat High Court at Ahmedabad.

TERMS AND CONDITIONS:

1. These appointments shall be for a period of three years.

2. No Retainer or Monthly remuneration will be paid to these appointees.

3. Shri Haroobhai Mehta, Senior Special Public Prosecutor will be incharge of such matters. He will mark cases to Shri Vivek Barot, Special Public Prosecutor appointed herein Gujarat High Court at Ahmedabad.

4. The appointees will be eligible for the fees as stated below:

- | | |
|---------------------------|---|
| (a) Drafting Complaint | Rs. 300/- per case. |
| (b) Effective hearing | (I) Rs. 300/- per Session i.e. forenoon or afternoon.
(II) Rs. 600/- if effective hearing takes place both in the forenoon and afternoon sessions. |
| (c) Non-Effective hearing | Rs. 200/- per day upto a maximum of 5 such hearings. |
| (d) Conference | Rs. 60/- per hour upto a maximum of 3 conferences. |

5. Shri Haroobhai Mehta, Senior Special Public Prosecutor and Shri Vivek Barot, Special Public Prosecutor shall not appear against the Union of India or any Central Government Officer and any Department of the Central Government in any criminal case referred to herein above in the High Court of Gujarat at Ahmedabad.

6. The appointment shall be terminable on one month's notice in writing on either side.

[F.No. 36(10)/90-Judl.]

P.C. KANNAN, Addl. Legal Adviser

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1994

मा. का. नि. 133-- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय में भारत के महारजिस्ट्रार और जननगना कार्य निदेशालय के कार्यालय में आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी "क" के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्न-लिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार और जननगना कार्यनिदेशालय का कार्यालय, आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी "क" समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य ग्रहणार्ह आदि:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, ग्रहणार्ह और उनसे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता : वह व्यक्ति:-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	जब पद अधिवा प्रचयन पद	सेवा में जाड़े गए वर्षों का	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
					फाबदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।	
1	2	3	4	5	6	7
आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी "क"	288* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" मराज-पत्रित, अनु-सचिवीय	1150-25-15000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण प्रत्यर्थियों की वसा में सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति/अनु-

सूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक, को जा सकता है)।

टिप्पण:-—आयु-सीमा भव-धारित करने के लिए निष्पत्ति तारीख भारत में अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (त कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा जम्मा जिले के पांगो उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
[अन्य अर्हताएं] विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोक्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

8	9	10
(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से बारहवां स्तर उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या समतुल्य अर्हता; और	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(ख) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए कम से कम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए।		
टिप्पण :—1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
टिप्पण :—2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित] रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		
टिप्पण :—3. आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रक्रमण मशीन (मशीनों) पर लिए गए गति परीक्षण द्वारा किया जाएगा।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

टिप्पण:—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर या लम्बी छुट्टी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर मनुष्य पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास न्यूनतम 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विशिष्ट अर्हताएं हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सार्वजनिक

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सब लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

13

14

1. भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के लिए (समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति)
 1. निदेशक (इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े प्रक्रमण) अध्यक्ष
 2. उप निदेशक (प्रशासन) सदस्य
 3. प्रत्यक्ष आकड़ा प्रविष्टि केन्द्र का भारसाधक अधिकारी सदस्य
 4. भारत सरकार के अन्य मंत्रालय/विभाग का केन्द्रीय सरकार का एक समूह "क" अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो सदस्य
11. जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति:
 1. जनगणना कार्य निदेशक या जनगणना कार्य संयुक्त निदेशक या जनगणना कार्य उप निदेशक या जनगणना कार्य सहायक निदेशक (तकनीक) अध्यक्ष
 2. जनगणना कार्य संयुक्त निदेशक या जनगणना कार्य उप निदेशक या जनगणना कार्य सहायक निदेशक (तकनीक) सदस्य
 3. केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय का केन्द्रीय सरकार का एक समूह "क" अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो सदस्य

लागू नहीं होता

[फा. स. 10/9/93-प्रार. जी. (प्र.-II)]

पी. एन. सिंह, अधीक्षक सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of the Registrar General, India)
New Delhi, the 22nd February, 1994

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby make, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator Grade 'A' in the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India and Directorate of Census Operations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India and the Director of Census Operations Data Entry Operator Grade 'A' Group 'C' post Recruitment Rules, 1993

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons or posts.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special Categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Data Entry Operator Grade 'A'	288* (1993) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted. Non-Ministerial	Rs. 1150-25-1500

Whether selection post or non-selection post. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 Age limit for direct recruits.

5	6	7
Not applicable	Not applicable	25 years' (Relaxable for Government employees upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note.—

The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim and Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti district, and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of rectt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10	11
<p>(a) 12th Standard pass certificate from any recognised Board/University or equivalent qualifications and,</p> <p>(b) should possess a speed of not less than 8000 key Depressions per Hour for Data Entry work.</p> <p>Note.1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates belonging to Scheduled, Castes/Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection</p>	Not applicable.	Two years	<p>Direct recruitment.</p> <p>Note.—Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a deputation of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Col. 8.</p>

Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Note 3—The speed of 8000 key Depressions per hour for Data entry work is to be judged by conducting a speed test on the Electronic Data Processing Machine(s), by the Staff Selection Commission.

In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Not applicable.	<p>I. Group 'C' DPC for Office of Registrar Genl. India.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director (Electronic Data Processing)—Chairman. 2. Deputy Director (Administration)—Member. 3. Officer incharge of Direct Data Entry Centre—Member. 4. A group 'A' Central Government Officer of other Ministry/Department of Government of India belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member <p>II. Group 'C' Departmental Promotion Committee for the office of the Director of Census Operations.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director of Census Operations or Joint Director of Census Operations or Deputy Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical)—Chairman 2. Joint Director of Census Operations or Deputy Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical)—Member. 3. A Group 'A' Central Government Officer of another Central Government Office, belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member. 	Not applicable.

कार्मिक लोक शिक्षाएत एवं पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1994

सा. का. नि. 134.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 18 सितम्बर, 1993 के पृ. 1399 पर प्रकाशित भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिक्षाएत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 461, तारीख 30 अगस्त, 1993 में,—

- (1) प्रथम परन्तुक में, “15 सितम्बर, 1993 के दिन” के स्थान पर “25 सितम्बर, 1993” पढ़ें।
- (2) द्वितीय परन्तुक में, “15 सितम्बर, 1993 के दिन के पहले और 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पायनियर के रूप में भर्ती या पुनः पदाभिहित किया गया समूह “घ” कर्मचारी” के स्थान पर “25 सितम्बर, 1993 के पहले पायनियर के रूप में भर्ती या, पुनः पदाभिहित किया गया समूह “घ” कर्मचारी, 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर,” पढ़ें।

[संख्या 25012/2/86—स्था. (क)]

वी. नटराजन, उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(Deptt. of Personnel & Training)

CORRIGENDA

New Delhi, the 3rd February, 1994

G.S.R. 134.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Deptt. of Personnel and Training) number G.S.R. 461, dated the 30th August, 1993 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 18th September, 1993, at page 1400,—

- (i) in line 10,—
for “proviso” read “provisos”
- (ii) in line 14,—
(a) for “(GRPF)” read “(GREF)”; and
(b) for “1953” read “1993”.

[No. 25012/2/86-Estt.(A)]

V. NATARAJAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1994

सा. का. नि. 135.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए एतद्वारा भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता (समूह “ग” पद) भर्ती नियम, 1987 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (i) भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता (समूह “ग” पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1993 कहा जाएगा।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता (समूह “ग” पद) नियम, 1987 की अनुसूची में क्रम संख्या 2 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

“लेखाकार”

[एफ. संख्या 11/13/93—सिक्का 1]]

शालिनी प्रसाद, अधर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दि. 3-1-1987 की सा. का. नि. संख्या 7 के अनुसार प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 10th January, 1994

G.S.R. 135.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President here by makes the following rules further to amend to India Government Mint, Calcutta (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 1987 namely :—

- (i) There rules may be called the India Government Mint, Calcutta (Group ‘C’ posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1993.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to India Government Mint, Calcutta (Group ‘C’ posts) Rules, 1987 for serial number 2 the following entry shall be substituted against the existing entry :—

“Accountant”

[File No. 11/13/93-Coin. 1]

SHALINI PRASAD, Under Secy.

Footnote:—Principal Rules were published vide GSR No. dated 3-1-1987.

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1994

सा. का. नि. 136.—इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 27(3) के साथ एडिशन, ई. गा. रा. मु. वि. अधिनियम, 1985 (1985 का 50) की धारा 27 के अन्तर्गत प्रबंध बोर्ड प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 जनवरी, 1991 के राजपत्र साधारण सांविधिक नियम 42 में अधिसूचित “प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों के लिये विनियम” में खंड 1, 6, 12 तथा नये खंड 13 में संशोधन/परिवर्धन करता है :—

उपर्युक्त उल्लिखित खंडों को संशोधन तथा परिवर्धन के पश्चात् इस प्रकार से पढ़ा जाएगा।

“1. प्रबंध बोर्ड की बैठक की तिथि कुलपति द्वारा निर्धारित की जाएगी जो बोर्ड के अध्यक्ष हों हैं।

6. जब प्रबंध बोर्ड की बैठक विधिवत् बुलाई गई हो और बैठक के लिये निर्धारित समय के आधे घंटे के अंदर यदि कोरम पूरा नहीं होता तो बोर्ड के सदस्यों के निर्णय के अनुसार अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय या ऐसे ही अन्य दिन, अन्य समय तथा स्थान के लिये बैठक स्थगित कर वा अकेलीस्किंग तथा बैठक की सूचना प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्यों को भेज दी जायेगी। यदि निर्धारित समय के आधे घंटे के अंदर कोई कोरम पूरा नहीं होता तो उपस्थित सदस्यों द्वारा ही कोरम निर्मित होगा।

12. विनियमों में संशोधन, निरसन तथा परिवर्धन करने की शक्ति प्रबंध बोर्ड में निहित है।

13. ये विनियम प्रबंध बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी लिपि से प्रवृत्त होंगे”

[सं. जी./विधि./2/90]

क. नारायणन, कुल सचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 23rd February, 1994

G.S.R. 136.—In exercise of the powers vested with it, under Section 27 of the IGNOU Act, 1985 (50 of 1985), read with Statute 27 (3) of the Statutes of the University, the Board of Management makes amendments/additions to Clauses, 1, 6, 12 and a new Clause 13, in the “Regulations for the meetings of the Board of Management” notified in the Gazette GSR-42 dated the 19th January, 1991:—

The Clauses referred above would read as below after amendment/addition:

“1. The date for a meeting of the Board of Management shall be fixed by the Vice-Chancellor, who is the Chairman of the Board.

6. Where a meeting of the Board of Management has been duly convened and no quorum is present within half an hour of the time appointed for the meeting, the meeting will be adjourned to the same day and time in the next week or to such other day and at such other time and place, as the members of the Board may decide, and notice for the adjourned meeting shall be sent to all the members of the Board of Management. If no quorum is present at an adjourned meeting within half an hour of the appointed time, the members present shall constitute the quorum.

12. The power to amend, repeal or add to these Regulations shall vest with the Board of Management.

13. These Regulations shall come into force from the date of their approval by the Board of Management.”

[No. G/Regu. 2/90]

K. NARAYANAN, Registrar

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1994

सा.का.नि. 137.—राष्ट्रपति, मूल नियम के नियम 45 के उपबंधों का अनुसरण करते हुए, भारतीय खान

ब्यूरो में निवास-स्थान के आबंटन की बाबत निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खान ब्यूरो (निवास-स्थान) का आबंटन नियम, 1993 है।
- (2) ये ऐसे आवासीय भवनों के आबंटन और सभी के प्रबंध को लागू होंगे जो भारतीय खान ब्यूरो के प्रादेशिक, उप प्रादेशिक या मुख्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और जो उन प्रादेशिक, उप प्रादेशिक या मुख्यालयों में नियोजित अधिकाधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को आबंटित किए जाने के लिए हैं।
- (3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :—

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) “आबंटन” से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार निवास-स्थान के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति देना अभिप्रेत है।
- (ख) “आबंटन वर्ष” से 1 जनवरी को प्रारम्भ होने वाला और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाला वर्ष या ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है जो भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए।
- प्रत्येक आबंटन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, नए सिरे में आवेदन मांगना अपेक्षित है।
- (ग) “महा नियंत्रक” से भारतीय खान ब्यूरो का, जो कि भारत सरकार, खान मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, प्रधान अभिप्रेत है।
- (घ) “प्राधिकृत अधिकारी” से महानियंत्रक द्वारा इन नियमों के निबंधनों के अनुसार उसके निमित्त कार्य करने के लिए प्राधिकृत भारतीय खान ब्यूरो का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।
- (ङ) “पात्र अधिकारी” से भारतीय खान ब्यूरो के ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृन्द अभिप्रेत हैं जो उस वर्ग/टाइप के निवास-स्थान के आबंटन के लिए पात्र हैं, जो उन्हें नियम 5 के अधीन अनुज्ञेय है और जो उस स्टेशन पर जहाँ निवास-स्थान स्थित है झूटी पर निवास करने के लिए अपेक्षित हैं।

- (च) “उपलब्धि” से मूल नियम के नियम 9 के उप-नियम (21) के खंड (क) के अधीन यथा परिभाषित वेतन अभिप्रेत है;

- (2) किराए की घसूली के प्रयोजन के लिए मूल नियम 45 (ग) में यथा परिभाषित उपलब्धि, किन्तु प्रतिकरात्मक भत्तों को अपवर्जित करते हुए, अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण :—निलम्बित अधिकारी के मामले में “उपलब्धियों” से वे उपलब्धियां मानी जाएंगी जो उसने उस आवंटन वर्ष के प्रथम दिन प्राप्त की है जिसमें वह निलम्बित किया गया है अथवा, यदि वह आवंटन वर्ष के प्रथम दिन ही निलम्बित किया गया है तो जो उसके द्वारा उस तारीख के ठीक पहले प्राप्त की गई है;

- (छ) “कुटुम्ब” से अभिप्रेत है, यथास्थिति पत्नी अथवा पति और सतान, सौतेली सतान वैध रूप से दत्तक ली गई संतान, माता-पिता, भाई, अथवा बहनें, जो समान्यतया अधिकारी के साथ निवास करते हैं और जो उस पर आश्रित हैं;
- (ज) “सरकार” से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;
- (झ) अधिकारी जिस प्रकार के निवास-स्थान का पात्र है, उसके संबंध में अधिकारी की “पूर्विकता तारीख” से वह पूर्वतम तारीख अभिप्रेत है जब से वह, छुट्टी की अवधि के सिवाय, निरन्तर उतनी उपलब्धियां केंद्रीय सरकार अथवा अन्यत्र सेवा के अधीन पद पर प्राप्त करता रहा है जो उसे किसी विशिष्ट टाइप अथवा किसी उच्चतर टाइप के आवंटन के लिए सुसंगत है:

परन्तु टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी के निवास-स्थानों के संबंध में, वह तारीख जब से अधिकारी केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा में, जिसमें अन्यत्र सेवा की अवधि भी है, निरन्तर रहा है, उसकी उस टाइप के लिए पूर्विकता तारीख होगी:

परन्तु यह और कि जहां दो या अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तारीख एक ही हो वहां उसके बीच ज्येष्ठता उपलब्धियों की राशि से अवधारित की जाएगी, अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी को कम उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी से अग्रता दी जाएगी, और जहां उपलब्धियां समान हैं वहां ज्येष्ठता सेवा काल की दीर्घता के अनुसार अवधारित की जाएगी।

- (अ) “अनुज्ञप्ति ‘फीस’” से इन नियमों के अधीन आवंटित निवास-स्थान के संबंध में मूल नियमों के उपबंधों के अनुसार मासिक रूप से देय धन-राशि अभिप्रेत है;
- (ट) “निवास स्थान” से ऐसा निवास स्थान अभिप्रेत है जो तत्समय महा-नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण में है और जिसे ये नियम लागू होते हैं।
- (ठ) “शिकमी देने” में किसी आवंटिती द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ उस अन्य व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्ति

फीस का संदाय करने पर अथवा उसके बिना आवास सुविधा का सहभोग करना आता है।

स्पष्टीकरण :—आवंटिती द्वारा अपने निकट संबंधियों के आवास-सुविधा का सहभोग शिकमी देना नहीं समझा जाएगा।

- (ड) “अस्थायी स्थानांतरण” से ऐसा स्थानांतरण अभिप्रेत है जिसमें अनुपस्थिति की अवधि चार मास के अनधिक हो;
- (ढ) “स्थानांतरण” से वर्तमान स्टेशन से किसी अन्य स्थान को अथवा किसी पात्र कार्यालय से किसी अपात्र कार्यालय को, स्थानांतरण अभिप्रेत है और इसमें मूल संगठन को स्थानांतरण अथवा प्रति-वर्तन और किसी अपात्र कार्यालय अथवा संगठन में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति भी आती है;
- (ण) किसी अधिकारी के संबंध में “टाइप” से निवास-स्थान का वह टाइप अभिप्रेत है जिसका वह इन नियमों के नियम 5 के उपबंध के अधीन पात्र है।

3. मकान का स्वामित्व रखने वाले अधिकारियों को आवंटन :—

- (1) इस नियम में—

- (क) “लगी हुई नगरपालिका” से ऐसी नगरपालिका अभिप्रेत है जो किसी स्थानीय नगरपालिका से लगी हुई है;
- (ख) किसी अधिकारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के संबंध में “मकान” से ऐसा भवन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है जिसका प्रयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो और जो स्थानीय नगरपालिका या किसी लगी हुई नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर स्थित हो।

स्पष्टीकरण :—किसी भवन का कोई भाग जिसका प्रयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है उस खंड के प्रयोजनों के लिए इस बात के होते हुए, भी मकान समझा जाएगा कि उसका कोई भाग अनिवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।

- (ग) किसी अधिकारी के संबंध में “स्थानीय नगरपालिका” से वह नगरपालिका अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर उस अधिकारी का कार्यालय स्थित है;
- (घ) किसी अधिकारी के संबंध में “कुटुम्ब के सदस्य” से यथास्थिति पति या पत्नी या अधिकारी की उस पर आश्रित सन्तान अभिप्रेत है;
- (ङ) “नगरपालिका” के अन्तर्गत नगर निगम, नगरपालिका समिति या बोर्ड, टाउन एरिया समिति,

नोटोफाइड एरिया समिति और छावनी बोर्ड आते हैं।

2. कोई अधिकारी, जो अपनी झूटी के स्थान या लगी हुई नगरपालिका में या तो अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में किसी मकान का स्वामी है, उसको आबंटित की गई सरकारी वास सुविधा के लिए अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर सरकारी निवास-स्थान के आबंटन के लिए ऐसी दर पर पात्र होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

3. जब कोई सरकारी निवास-स्थान किसी अधिकारी को आबंटित हो जाने के पश्चात् वह या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य अपनी झूटी के स्थान या लगी हुई नगरपालिका में किसी मकान का स्वामी बन जाता है तो ऐसा अधिकारी उस तथ्य को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् महानियंत्रक/प्राधिकृत अधिकारी को उस तारीख से जिसको मकान पूरा होने की तारीख को किराए पर दिया जाता है या अधिभोग में लिये जाता है, इनमें से जो भी पूर्वसर हो, एक मास की अवधि के भीतर अधिसूचित करेगा।

4. ऐसे अधिकारियों को निवास-स्थान का आबंटन जो पति और पत्नी हैं—ऐसे अधिकारियों के मामलों में प्रावधान :

(1) किसी अधिकारी की यथास्थिति, जिसकी पत्नी या जिसके पति को पहले ही निवास-स्थान आबंटित किया जा चुका है, इन नियमों के अधीन कोई निवास-स्थान तब तक आबंटित नहीं किया जायेगा जब तक ऐसा निवास-स्थान अव्यपित नहीं कर दिया जाता :

परन्तु यह उपनियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किये गये न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक्-पृथक् निवास कर रहे हैं।

(2) जहाँ दो अधिकारी, जो इन नियमों के अधीन पृथक् रूप से आबंटित निवास-स्थानों के अधिभोगी हैं, एक दूसरे से विवाह कर ले वहाँ वे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास-स्थानों में से एक अव्यपित कर देंगे।

(3) यदि निवास-स्थान का अव्यपण उपनियम (2) की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता तो निम्नतर टाइप के निवास-स्थान का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द समझा जायेगा और यदि निवास-स्थान एक ही टाइप के हैं तो महानियंत्रक के विनिर्देशानुसार उनमें से एक का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द समझा जायेगा।

(4) जहाँ पति और पत्नी दोनों ही भारतीय जवान व्यूरो के अधीन नियोजन में हैं, वहाँ उन दोनों में से प्रत्येक के इन नियमों के अधीन निवास-स्थान के आबंटन के हक पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जायेगा।

(5) उपनियम (1) से (4) तक में किसी बात के होते हुए भी:—

(क) यदि, यथास्थिति, पत्नी या पति को, जो इन नियमों के अधीन निवास-स्थान का आबंटित है, ऐसे पूल से, जिसे ये नियम लागू नहीं होते, एक ही स्टेशन पर बाध में निवास-स्थान संबंधी कोई आवश्यकता आबंटित कर दी जाती है तो

यथास्थिति पत्नी या पति ऐसे आबंटन के एक मास के भीतर इन निवास-स्थानों में से कोई एक अव्यपित कर देगा:

परन्तु यह खंड वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किये गये न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक्-पृथक् निवास कर रहे हैं।

(ख) जहाँ दो अधिकारी, जो एक ही स्टेशन पर ऐसे पृथक् निवास स्थानों के अधिभोगी हैं जिनमें से एक निवास-स्थान इन नियमों के अधीन आबंटित किया गया है और दूसरे ऐसे पूल से आबंटित किया गया है जिसे ये नियम लागू नहीं होते, एक दूसरे से विवाह कर लें, वहाँ कोई भी एक अधिकारी ऐसे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास-स्थानों में से किसी एक का अव्यपित कर देगा।

(ग) यदि निवास-स्थान का अव्यपण खंड (क) या खंड (ख) की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता तो साधारण पूल में के निवास-स्थान का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द समझा जायेगा।

6. निवास-स्थानों का वर्गीकरण—(1) आबंटन के प्रयोजन के लिए निवास स्थानों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन नियमों द्वारा अव्यपण उपबंधित के विवाह, अधिकारी नीचे दी गई शर्तों में दक्षिण टाइप के निवास-स्थान के आबंटन का पात्र होगा :-

निवास स्थान का टाइप	उस आबंटन व्यय के, जिसमें आबंटन किया गया है, प्रथम दिन की मासिक उपलब्धियाँ
टाइप 1	950/रुपये प्रति मास से कम
टाइप 2	1500/रु. प्रति मास से कम किन्तु 950/- रुपये प्रति मास से कम नहीं।
टाइप 3	2800/- रुपये प्रति मास से कम किन्तु 1500/-रुपये प्रति मास से कम नहीं।
टाइप 4	3600/-रुपये प्रति मास से कम किन्तु 2800/-रुपये प्रति मास से कम नहीं।
टाइप 5	5900/-रुपये प्रति मास से कम किन्तु 3600/- रुपये प्रति मास से कम नहीं।
टाइप 6	7300/-रुपये प्रति मास से कम किन्तु 5900/-रुपये प्रति मास से कम नहीं।
टाइप 7	8000/-रुपये प्रति मास से कम किन्तु 7300/-रुपये प्रति मास से कम नहीं।

(2) टाइप 5 और उपर के टाइप के लिये पात्र अधिकारी ठीक निम्नले टाइप के निवास स्थान के लिये भी पात्र होगा।

7. आबंटन तथा व्यय के अवधारण के लिये आवेदन—

प्रत्येक अधिकारी, जो इन नियमों के अधीन आबंटन कराना चाहता है, संबंधित कार्यालय में झूटी पर रिपोर्ट करने के एक मास के भीतर इन नियमों के उपबंध में दिये गये प्रारूप “क” में एक आवेदन महानियंत्रक को या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

ऐसे पात्र अधिकारी को व्ययता जो स्थायी या अस्थायी पद धारण कर रहे हैं, निवास-स्थान के आबंटन के प्रयोजन के लिये, इन नियमों के अधीन निवास-स्थान के प्रत्येक वर्ग के लिये विहित वेतन की अर्हता सीमा पर पहुंचने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी।

परन्तु यदि एक ही ज्येष्ठता के दो या अधिक अधिकारी पात्र हैं तो उनके बीच ज्येष्ठता उपलब्धियों की रकम के अनुसार अवधारित की जायेगी, उच्चतर उपलब्धियों को ठीक नीचे की उपलब्धियों पर प्रभुता दी जायेगी अथवा जहाँ उपलब्धियाँ बराबर हैं वहाँ आवेदन के समय ऐसे अधिकारी द्वारा धारित पद में उन उपलब्धियों को प्राप्ति करने की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी—दोषपूर्ण अवधि को ठीक नीचे की अवधि पर प्रभुता दी जायेगी। जब ज्येष्ठता और उपलब्धि बराबर हों तो उस अधिकारी को प्राथम्यता दिया जायेगा जो आयु में बड़ा हो।

8. निवासस्थानों का आबंटन :—

(1) इन नियमों में अथवा उपबधित के निशान, किमी निवास-स्थानों के खाली होने पर वह भारतीय खान बंदूकों के महानियंत्रक द्वारा अधिमानतः उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जो उस टाईप की आवास सुविधा का परिवर्तन चाहता है और यदि उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित न हो तो उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जिसके पास उस टाईप की आवास सुविधा नहीं है और जिसकी उस टाईप के निवास स्थान के लिए पूर्णता तारीख सबसे पहले हो। यह आबंटन निम्नलिखित शर्तों पर होगा, अर्थात् :—

(i) उप टाईप में उच्चतर टाईप का निवास स्थान जिसके लिए आवेदक पात्र है, उस दशा के सिवाय जब उस टाईप की आवास सुविधा, जिसका वह पात्र है उपलब्ध न हो सामान्यतः आबंटित नहीं किया जाएगा। कोई आवेदक इस बात के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि वह जिस टाईप के निवासस्थान का पात्र है उससे निम्नतर टाईप का निवास स्थान स्वीकार करे और यदि हाथ वाला टाईप उपलब्ध नहीं है तो निम्नतर टाईप इस शर्तों के अधीन रहते हुए आबंटित किया जा सकता है कि जब हकबाला टाईप आबंटन के लिए उपलब्ध हो और वह उसे आबंटित कर दिया जाए तब आवेदक को निम्नतर टाईप खानी करना होगा।

(ii) किसी निम्नतर कोमिट के निवास स्थान के आबंटन के लिए किसी आवेदक की प्रार्थना पर उसे ऐसे टाईप से ठीक निम्नतर टाईप का निवासस्थान आबंटित किया जा सकता है जिसके लिए आवेदक नियम 5 के अधीन उसके लिए अपनी पूर्णता तारीख के आधार पर पात्र है।

परन्तु यदि अधिकारी के अधिभोग में का निवास स्थान सरकारों कार्य के लिए खाली किया जाना अपेक्षित है तो महानियंत्रक किसी अधिकारी के विद्यमान आबंटन को रद्द कर सकेगा और उसे उसी टाईप का प्राथमिक निवास स्थान या आवास परिस्थितियों में अधिकारी के अधिभोग में के निवास स्थान के टाईप का निवास स्थान आबंटित कर सकेगा।

(2) प्रस्थायी पद का धारक जिसे निवास स्थान आबंटित किया जाता है, यदि उसे किसी ऐसे निम्नतर पद पर किसी समय प्रतिवर्तित किया जाता है जो उसे आबंटित आवास सुविधा के बगैरे के लिए हकदार नहीं बनाता है तो वह निम्नतर बगैरे के निवास स्थान में, जैसे ही यथाशीघ्र कोई ऐसा निवास स्थान उसे उपलब्ध किया जाता है, प्रतिवर्तित हो जाएगा।

9. कतिपय प्रवर्गों के अधिकारियों के लिए पृथक पूरों का बहाल रखना :—

(1) इन नियमों में किसी बात के होने हुए भी, निम्नलिखित पूल बनाए रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(i) महिला अधिकारियों का पूल विवाहित महिला अधिकारियों के लिए और अविवाहित महिला अधिकारियों के लिए, पृथक: स्पष्टीकरण

(क) विवाहित महिला अधिकारी में ऐसी महिला अधिकारी अभिप्रेत है, जिसका विवाह अस्तित्व में है और जो अपने पति से स्थायिक रूप से प्रथक नहीं हुई है।

(ख) "अविवाहित महिला अधिकारी" से ऐसी महिला अधिकारी अभिप्रेत है, जो विवाहित महिला अधिकारी नहीं है।

2. इस पूल में रहे ताँ शर्तें निम्न स्थानों का संस्था और टाईप विभाग द्वारा समय समय पर अवधारित किये जाएंगे।

3. अधिकारी उक्त पूल में उस टाईप से ठीक निम्नतर टाईप में आवास सुविधा के आबंटन के हकदार होंगे जिसके वे नियम 5 के उपबंधों के अधीन हकदार हैं।

4. इस नियम के अधीन निशान स्थानों के आबंटन के लिए पात्र अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) महिला अधिकारियों के पूल में, उस पूर्वकता तारीख के आधार पर जिस तारीख को ऐसी प्रत्येक अधिकारी उस पूल में निवास स्थान के उस टाईप की पात्र हुई थी।

10. पारी बाह्य आबंटन

नियम 7 के उपबंधों में किसी बात के होने हुए भी, महानियंत्रक द्वारा निवास स्थान का आबंटन पारी बाह्य आधार पर किसी अधिकारी को उसके स्वयं के गम्भीर रूप में रुग्ण होने के आधार पर या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के कुटुम्ब यन्त्रा केन्द्र/रुद्ध रोग के ग्रस्त होने तथा शारीरिक रूप से निश्चयना आदि (जैसे कि नीचे संलग्न विवरण के अनुसार है के आधार पर विहित चिकित्सा प्राधिकारी के परामर्श से किया जा सकता है। ऐसे मामलों में आबंटन पारी बाह्य आवेदन की वस्तुतः प्राप्ति तारीख के अनुसार हक प्राप्ति टाईप के क्वार्टर की उपलब्धता के अधीन रहने हुए, किया जा सकेगा यदि हक वाले टाईप का क्वार्टर तुरंत उपलब्ध नहीं है तो ठीक नीचे के टाईप के आबंटन के लिए यदि तुरंत उपलब्ध हो, तभी विचार किया जाएगा।

रोग का नाम	हक	चिकित्सा प्रमाणपत्र/सक्षम प्राधिकारी
1	2	3
हृदय रोग	सरकारी मेडिक (केवल स्वयं)	श्रेणी III या IV के लक्षणों युक्त प्रमाण-पत्र जो हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा दिया गया हो और संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रति हस्ताक्षरित हो।
केंसर	स्वयं सरकारी मेडिक और उनके कुटुम्ब अर्थात् पत्नी/पति तथा सन्तान की रुग्णता	सक्रिय अवस्था में बुद्धिमत् अस्पतात्मक केंसर जो संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रति हस्ताक्षरित हो।
कुष्ठरु रोग	यथोक्त	कुष्ठरु रोग सक्रिय अवस्था में जिसमें अन्य व्यक्तियों को जोखिम हो सकता हो और धन धूल जो संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रति हस्ताक्षरित हो।

(1)	(2)	(3)
शारीरिक निःशक्तता	सरकारी सेवक (केवल स्वयं)	शारीरिक निःशक्तता 40% (असमर्थता) की सीमा तक संबंधित अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाणपत्र जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो।
अंधता (शारीरिक निःशक्तता के प्रवर्ग)	-यथोक्त-	संघ अधीन वे व्यक्ति जो निम्नलिखित किसी अवस्था से ग्रस्त हैं: (क) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव; (ख) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर दृष्टि में 67/6 या 20/200 (स्नेन) से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता; (ग) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के सम्मुख होना या अधिक खराब होना।
बधिर (शारीरिक सरकारी सेवक निःशक्तता के प्रवर्ग)	(केवल स्वयं)	बधिर वे हैं जिसमें श्रवण शक्ति का आधार जीवन के सामान्य प्रयोजनों के लिए निष्क्रिय है।

10. आबंधन या प्रस्थापना का स्वीकार न किया जाना अथवा आबंधित निवास स्थान को स्वीकार करने के पश्चात् अधिभोग में लेना, मकाम किराया भत्ता लेना ;

(1) यदि कोई अधिकारी किसी सरकारी निवास स्थान का आबंधन स्वीकार करने में असफल रहता है तो वह एक वर्ष की अवधि पर्यंत दूसरे आबंधन का पात्र न होगा और नियम 10(3) के निबंधनों के अनुसार ही मकान किराया प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) यदि किसी अधिकारी को, जिसके अधिभोग में किसी निम्नतर टाइप का निवास स्थान है, ऐसे टाइप का निवासस्थान आबंधित किया जाता है जिसके लिए वह नियम 5 के अधीन पात्र है तो उसे उस आबंधन को या आबंधन की प्रस्थापना को अस्वीकार कर देने पर, पूर्वतन आबंधित निवासस्थान में रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञात किया जा सकता है, अर्थात्:--

(क) ऐसा अधिकारी उस आबंधन आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के लिए उच्चतर वर्ग की आवास सुविधा के आबंधन के लिए पात्र नहीं होगा;

(ख) वर्तमान निवासस्थान छोड़े रहने के दौरान उस पर बही अनुज्ञप्ति फौस प्रभारित की जाएगी, जो उसे गू. नि. 45-क के अधीन इस प्रकार आबंधित या प्रस्थापित निवासस्थान के लिए संदल करने पड़ती अथवा वह अनुज्ञप्ति फौस जो उस निवासस्थान के लिए देय है जो पहले ही उसके अधिभोग में है, दोनों में से जो अधिक हो।

(3) यदि प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी हक वाले टाइप की आवास-सुविधा आबंधित करने को स्थिति में नहीं है तो वह महा-नियंत्रक, भारतीय खान-भूरो की ओर से "आवास-सुविधा न होने का प्रमाण-पत्र" जारी करेगा। कर्मचारी द्वारा "आवास-सुविधा न होने का प्रमाण-पत्र" के प्रस्तुत करने पर, कर्मचारी को "आवास-सुविधा न होने का प्रमाण-पत्र" की तारीख से मकाम किराया भत्ता संदेय होगा।

11. प्रकीर्ण:

महानियंत्रक केन्द्रीय सरकार के विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी, ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, इस शर्त के अधीन क्वार्टर आबंधित कर सकेंगे कि भारतीय खान भूरो से आबंधन के लिए कोई आवेदक नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति फौस, जल और विद्युत प्रभारों का संवाद करना होगा तथा वे भारतीय खान भूरो के निवास स्थान आबंधन नियमों द्वारा शासित होंगे। ऐसे आबंधन नष्ट किए जा सकेंगे जब निवास-स्थान अधिक हों और भारतीय खान भूरो की ओर से मांग कम हो और ऐसा आबंधित भारतीय खान भूरो के आबंधन नियमों द्वारा शासित होगा।

(ख) आबंधन महानियंत्रक द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या इन नियमों के किसी उद्देश्य के अधीन रद्द किया गया नहीं समझा जाता;

(ग) आबंधन उस अधिकारी द्वारा अग्रपिप्त नहीं कर दिया जाता;

(घ) अधिकारी निवास-स्थान का अधिभोग समाप्त नहीं कर देता।

2. अधिकारी उसे आबंधित निवास-स्थान को उपनियम (3) के अधीन रहते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी के होने पर उस अवधि-पर्यन्त अपने पास रख सकता है जो उस सारणी के स्तम्भ (2) में सतम्बधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है: परन्तु यह तब जब कि वह निवास-स्थान उस अधिकारी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए अग्रपिप्त हो

12. आबंधन प्रभावी रहने की अवधि और तत्पश्चात् कबजा बनाए रखने का रियायती प्रभार:--

(1) आबंधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि--

(क) अधिकारी के उस विनिर्दिष्ट स्टेशन में कर्तव्यारूढ़ न रह जाने के पश्चात् वह रियायती अवधि समाप्त नहीं हो जाती जो उप-खंड (2) के अधीन अनुज्ञेय है;

घटनाएं	निवास स्थान अपने पास रखने की अनुज्ञेय अवधि
1	2
(i) पदत्याग, पदच्युति या सेवा से हटाया जाना या सेवा का पर्यवसान	एक मास
(ii) सेवा निवृत्ति या सेवान्तर छुट्टी	चार मास
(iii) आबंधित की मृत्यु	छह मास
(iv) निवास-स्थान के आबंधन के स्टेशन से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानांतरण	दो मास
(v) भारत में अग्रपिप्त सेवा पर जाना	दो मास
(vi) भारत में अस्थायी स्थानांतरण अथवा भारत से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानांतरण	चार मास
(vii) छुट्टी (जो सेवा निवृत्ति-पूर्व छुट्टी, मस्थीकृत छुट्टी, सेवात छुट्टी, चिकित्सीय छुट्टी या अध्ययनार्थ छुट्टी से भिन्न हो)	छुट्टी की अवधि पर्यन्त किन्तु चार मास से अधिक नहीं।

1	2
(viii) सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी या मू नि 86 के अधीन दी गई प्रत्योष्ठन छुट्टी	पूरे औसत वेतन पर छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त किन्तु चार मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, इस में सेवा निवृत्ति की वषा में अनुज्ञेय अवधि की सम्मिलित है।
(ix) भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए, बाजार बिराये के संवाय के सिवाय छह मास से अधिक नहीं।
(x) चिकित्सीय आधार पर छुट्टी (भारत की छुट्टी से भिन्न)	छुट्टी की अवधि पर्यन्त किन्तु छठ मास से अधिक नहीं।
(xi) तपेदिक, कैंसर या ऐसी अन्य गम्भीर प्रकृति की रुग्णता के आधार पर चिकित्सीय छुट्टी।	छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त
(xii) प्रशिक्षणीय या अध्ययनार्थ छुट्टी जाने पर	प्रशिक्षण या अध्ययन की पूर्ण अवधि पर्यन्त।

स्पष्टीकरण

(1) मद (iv), (v), (vi) और (ix) के सामने वर्णित अन्तरण पर अनुज्ञेय अवधि की गणना, कार्यभार सौंपने तथा छुट्टी की उस अवधि की यदि कोई हो जो अधिकारी को मजूर की गई है और जो अधिकारी द्वारा नये कार्यालय में कर्तव्य भार ग्रहण करने के पूर्व सौंपी गई है तारीख में की जाएगी।

(2) जब कोई निवास-स्थान उपनियम (2) के अधीन रखेखा जाए तो अनुज्ञेय गिरावटी अवधि की समाप्ति पर वह आवंटन सिवाय उस दशा के जब उन अवधियों की समाप्ति के पश्चात् वह अधिकारी किसी ऐसे स्थान पर जहाँ उसे निवास-स्थान आवंटित किया गया है कर्तव्य भार ग्रहण कर लेता है रद्द किया गया समझा जाएगा।

(3) जब किसी कोई अधिकारी बिना वेतन और भत्तों के चिकित्सीय छुट्टी पर हो तो वह उपनियम (2) के नीचे दी गई मारणी की मद स (x) और (xi) के अधीन दी गई है तो के आधार पर अपने निवास स्थान को अपने पास रख सकता है परन्तु यह तब जब वह ऐसे निवास-स्थान के लिए अनुज्ञप्ति फीस प्रतिमास नकद भोजता रहता है और ऐसी फीस दो मास से अधिक तक न भेजने की दशा में आवंटन रद्द हो जाएगा।

13 अनुज्ञप्ति फीस विषयक उपबन्ध—

(1) आवास-सुविधा के आवंटन पर, अनुज्ञप्ति फीस और सेवा प्रभार मूल नियम के नियम 45 के अधीन प्रभावित किए जाएंगे और उनही कटौती अधिकारी के वेतन विल से की जाएगी। अनुज्ञप्ति फीस का वार्षिक अधिभोग की तारीख से अथवा आवंटन आदेश की प्राप्ति की तारीख के आठवें दिन से प्रारम्भ होगा, जब आवास-सुविधा या अनुकूलपी आवास-

सुविधा का आवंटन स्वीकार कर लिया जाए तो अनुज्ञप्ति फीस का वार्षिक अधिभोग की तारीख से अथवा आवंटन की प्राप्ति की तारीख के आठवें दिन से, जो भी पूर्वतर हो, प्रारम्भ होगा।

(2) जो अधिकारी उसे आवंटित आवास-सुविधा वा कच्चा आवंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर नहीं लेता उससे उस तारीख से एक मास अथवा उस विशिष्ट आवास-सुविधा के पुन आवंटित किए जाने, जो भी पूर्वतर हो, की अवधि तक अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी।

(3) जहाँ किसी अधिकारी को जिसके अधिभोग में एक निवास स्थान है दूसरा निवास-स्थान आवंटित किया जाता है और वह नए निवास-स्थान पर अधिभाग प्राप्त कर लेता है तब पुराने निवास-स्थान का आवंटन नए निवास-स्थान का अधिभोग प्राप्त करने की तारीख से रद्द समझा जाएगा। तथापि, निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए वह पहले निवास-स्थान को उस दिन तथा उसके बाद के एक दिन तक बिना अनुज्ञप्ति फीस दिए, अपने पास रख सकता है।

14 अधिकारी का अनुज्ञप्ति फीस देने का वैयक्तिक दायित्व तथा अन्वयायी सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रतिभू अवपत्र का दिया जाना—

(1) जिस अधिकारी को निवास-स्थान का आवंटन किया जाए उस पर उसकी अनुज्ञप्ति फीस के संदाय का तथा उस नुकसान का दायित्व होगा जो उचित टट-पूट के अनिवार्य उस निवास स्थान को अथवा सरकार द्वारा उसमें दिए गए फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग या सेवा-व्यवस्था को उस अवधि के दौरान पहुँचती है जब निवास-स्थान आवंटित कर दिया जाता है और उसे आवंटित रहता है या, जहाँ आवंटन इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द कर दिया गया हो वहाँ, जब तक निवास-स्थान खाली करके उसका पूर्णतः खाली रूप में कच्चा सरकार को वापस नहीं कर दिया जाता।

(2) जहाँ वह अधिकारी जिसे निवास स्थान आवंटित किया गया है न तो स्थायी सरकारी सेवक है और न स्थायी सरकारी सेवक है वहाँ वह सरकार द्वारा इस निमित्त बिलित प्रश्न में प्रति प्रतिनियुक्त एक प्रतिभू सहित निष्पादित करेगा। यह प्रतिभू केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने वाला समान या उच्चतर हैनियम का स्थायी सरकारी सेवक होना चाहिए। यह प्रतिभू अपने सभी किराये तथा अन्य ऐसे प्रभारों में सम्मिलित संदाय के लिए होगा जो उस निवास-स्थान की वास्तविकता के द्वारा देय हो।

(3) यदि प्रतिभू सरकारी सेवा में नहीं रह जाता या दिवालिया हो जाता है या अपनी प्रतिभूति वापस ले लेता है या किसी अन्य कारण से पात्र नहीं रह जाता है तो अधिकारी एक नया प्रतिभूति बंधपत्र उसके प्रतिभूति बंधपत्र रद्द किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगा और यदि वह ऐसा न करे तो उस निवास-स्थान का उसे आवंटन उस भटना की तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा।

(4) पानी और बिजली प्रभार आवंटित की द्वारा सञ्चित प्राधिकारियों द्वारा बिनिविष्ट दर और मीटर रीडिंग के अनुसार उक्त प्राधिकारी को सवत किए जाएंगे। जहाँ एक ही मीटर दिया गया हो वहाँ सन्नियंत्रक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या राज्य लोक निर्माण विभाग में परामर्श करके एक सपाट दर नियत करेगा और आवंटित उस दर के अनुसार संदाय करेगा।

15 आयुक्त का अध्ययन और सूचना की अवधि

(1) कोई अधिकारी इन नियमों के अधीन उसे आवंटित सरकारी आवास सुविधा को तब तक अध्ययन नहीं करेगा जब वह सन्नियंत्रक द्वारा या उसके निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नियम 11 के उपनियम (2) के अधीन अधिवर्षिक शर्तों की पूर्ति करने के अधीन

रहते हुए या किसी स्टेशन बाह्य कार्यालय में उसके स्थानांतरण की वशा में, उसे ऐसा करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात नहीं किया गया हो।

(2) जब उसे आर्बिट्रल अस्पष्टिप करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, तो—

(क) वह उसे आर्बिट्रल विधिगत निवास-स्थान पर कोई अधिकार नहीं बनाए रखेगा;

(ख) वह निवास-स्थान खाली करने की तारीख के कम से कम 10 दिन पूर्व निवास-स्थान अधिगति करने के अपने आशय की सूचना देगा यदि वह ऐसा नहीं करता है तो 10 दिन का किराया या उस अवधि का किराया जो 10 दिन से कम हो, प्रसारित किया जाएगा;

(ग) वह कोई मकान किराया भत्ता नहीं लेगा जब तक कि महानियंत्रक या उसके निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा वह विनिर्दिष्टतः मंजूर न किया जाए।

16. निवास-स्थान का परिवर्तन :—

(1) जिस अधिकारी को इन नियमों के अधीन निवास-स्थान का आर्बिट्रल किया गया है वह आवेदन कर सकता है कि उसको उसके बदले में उसी टाइप का निवास-स्थान दिया जाए। किसी अधिकारी को आर्बिट्रल एक टाइप के निवास स्थान की बावत केवल एक से अधिक परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) परिवर्तन महानियंत्रक के कार्यालय में परिवर्तन के लिए प्राप्त आवेदनों के क्रम में दिए जाएंगे।

(3) यदि कोई अधिकारी निवास-स्थान के परिवर्तन की प्रस्थापना आर्बिट्रल की प्रस्थापना के जारी किए जाने के पांच दिन के भीतर स्वीकार नहीं करता तो उसके नाम पर उस टाइप के निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए एक वर्ष तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

(4) जो अधिकारी, निवास-स्थान का परिवर्तन स्वीकार करने के पश्चात् उसका कच्चा नहीं लेता उससे ऐसे निवास-स्थान के लिए नियम 12 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी, जो उस निवास-स्थान के लिए, जो पहले ही उसके कब्जे में है, और जिसका आर्बिट्रल बराबर बना रहेगा, मूनि० 45 के अधीन प्रसामान्य अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त होगी।

17. कुटुम्ब के दर की मृत्यु की वशा में निवास-स्थान का परिवर्तन :—

नियम 15 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अधिकारी के कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और वह निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए, आवेदन ऐसी घटना के तीन मास के भीतर करता है तो उसे निवास-स्थान के परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकती है। परन्तु यह परिवर्तन उसी टाइप के निवास स्थान में होगा जिस टाइप का निवास स्थान उस अधिकारी को पहले से आर्बिट्रल है।

18. निवास-स्थानों का पारस्परिक विनियम :—

जिन अधिकारियों को इन नियमों के अधीन एक ही टाइप के निवास-स्थान एक ही स्टेशन में आर्बिट्रल किए गए हैं, वे महानियंत्रक को आवेदन कर सकते हैं कि उन्हें अपने निवास-स्थानों या पारस्परिक विनियम करने की अनुज्ञा दी जाए जब इस बात की उचित सोच पर प्रत्याशा हो कि दोनों अधिकारी ऐसे विनियम के अनुमोदन की तारीख से कम से कम छह माह तक उसी स्टेशन में कार्यरत रहें और पारस्परिक रूप से निवास स्थानों के विनियम में हितरहित हैं तब पारस्परिक विनियम की अनुज्ञा दी जा सकती है।

19. उन स्थानों के लिए स्थानांतरण जहाँ कुटुम्ब नहीं रखा जा सकता :—

यदि किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण किसी ऐसे स्थान को किया जाता है जहाँ उसे अपना कुटुम्ब साथ ले जाने के लिए सरकार द्वारा अनुज्ञा नहीं दी जाती या सनाह नहीं दी जाती और इन नियमों के अधीन उसे आर्बिट्रल निवास-स्थान उसके कुटुम्ब को उस स्टेशन में रहने के लिए अपेक्षित है तो उसे, प्रार्थना करने पर, मूनि० 45क के अधीन अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर निवास-स्थान रखने के लिए अनुज्ञा तब तक के लिए दी जा सकती है जब तक अधिकारी का ऐसा स्टेशन पर स्थायी तौर पर स्थानांतरण नहीं हो जाता जहाँ वह सरकार द्वारा अपने साथ अपने कुटुम्ब को ले जाने के लिए अनुज्ञात है।

20. निवास स्थान के रख-रखाव के लिए उत्तरदायित्व :—

(1) कोई अधिकारी, जिसे निवास स्थान आर्बिट्रल किया गया है, उस निवास स्थान और परिसर को महानियंत्रक या हम निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समामान्य रूप में साफ वशा में रखेगा।

(2) कोई अधिकारी, जिसे निवास स्थान आर्बिट्रल किया गया है, महानियंत्रक की अनुज्ञा के बिना परिसर में कोई पेड़ नहीं उगाएगा या किसी विद्यमान पेड़ को नहीं काटेगा या छटाएगा।

(3) किसी अधिकारी से, जिसे निवास स्थान आर्बिट्रल किया गया है निवास स्थान का अधिभोग प्रान करने समय यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फर्नीचर, फिटिंग आदि की जो उसे निवास स्थान में उपलब्ध कराई जाती तथा उसे हुए पेड़ों की भी तालिफ पर हस्ताक्षर करें।

21. निवास स्थान की शिकमी देना या सहभोग :—

(1) कोई अधिकारी अपने को आर्बिट्रल निवास स्थान या उनसे संबन्धित उपग्रहों, गैरजों और कमरों आदि का सहभोग भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारियों के साथ ही करेगा। सेवक निवासों (या क्वार्टरों) उपग्रहों, गैरजों आदि का उपयोग केवल उचित प्रयोजनों के लिए जिनके अन्तर्गत आर्बिट्रल का निवास भी है, या अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनकी महानियंत्रक अनुज्ञा दें।

(2) कोई अधिकारी अपने सम्पूर्ण निवास-स्थान को शिकमी नहीं देगा :

परन्तु छुट्टी पर जाने वाला अधिकारी अपने निवास स्थान में किसी अन्य अधिकारी को, जो सरकारी आवास सुविधा का सहभोग करने के लिए पात्र है, देखभाल करने वाले के रूप में छह माह से अधिक अवधि के लिए रख सकता है।

(3) जो अधिकारी अपने निवास स्थान का सहभोग करे या उसे शिकमी दे वह ऐसा अपनी जोखिम और उत्तरदायित्व पर करेगा और उस निवास-स्थान की बाबत देय कोई अनुज्ञप्ति फीस देने के लिये और ऐसे किसी नुकसान के लिये वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी बना रहेगा जो निवास स्थान को या उसकी सीमाओं या भूमियों को या सरकार द्वारा उसमें की गई सेवा व्यवस्थाओं को पहुंचे और जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त हो।

(4) निवास स्थान का सहभोग केवल महानियंत्रक की पूर्ण अनुज्ञा से ही अनुज्ञात किया जा सकेगा।

22. नियमों और शर्तों को भंग करने का परिणाम :—

(1) यदि वह अधिकारी जिसे निवास स्थान आर्बिट्रल किया गया है, सहभोगी से ऐसी दर पर किराया प्रभारित करने हुए जिसे महानियंत्रक अत्यधिक समझ, निवास स्थान शिकमी

देता है अथवा निवास स्थान या घर के किसी भाग में से कोई अप्राधिकृत निर्माण करना है अथवा निवास स्थान या उसके किसी भाग का उपयोग उन प्रयोजनों में भिन्न प्रयोजनों के लिये करना है जिनके लिये वह है अथवा बिजुली या जल के कनेक्शन को बिगाड़ता है अथवा नियमों या आर्बटन के निबंधनों और शर्तों को भंग करता है अथवा किसी ऐसे प्रयोजनों के लिये, जिन्हें महानियंत्रक अनुचित समझे, निवास स्थान या परिसर का उपयोग कर करता है और/अथवा स्वयं ऐसा आचरण करता है। महानियंत्रक का राय में उस अधिकारी के पत्रों से शान्तिपूर्ण संबंधों को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, अथवा आर्बटन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी आवेदन या लिखित कथन में कोई गलत जानकारी जानबूझ कर देता है, तो महानियंत्रक उस आनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उस अधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है, हो निवास स्थान का आर्बटन रद्द कर सकता है।

(2) यदि अधिकारी नियम 4(2), 20(4) में उपबंधित रूप में महानियंत्रक को अधिसूचित नहीं करता है या इस प्रकार कोई आवेदन या कथन अधिसूचित करते समय किसी तात्त्विक तथ्य को छिपाता है तो महानियंत्रक आर्बटन को उस तारीख से रद्द कर सकेगा जिनमें वह उस नियमों अधीन सरकारी आवास-सुविधा के आर्बटन के लिये अपाक्षक हुआ था।

(3) यदि कोई अधिकारी उसे आर्बटित निवास-स्थान को या उसके किसी भाग को या उससे संलग्न किसी उपग्रह, गैरेज या अस्तबल को इन नियमों का उल्लंघन करने शिकमी देता है तो, ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती है, उसके उतनी वर्षित अनुज्ञप्ति फीस की जा सकती है जो मूल नियम 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस के चार गुना से अधिक न हो।

(4) प्रत्येक मामले में इस बात का विनिश्चय कि कितनी अनुज्ञप्ति फीस घसूल की जाये महानियंत्रक गुणावगुण के आधार पर करेगा। इसके अतिरिक्त उस अधिकारी को भविष्य में ऐसी विनिश्चित अवधि पर्यंत, महानियंत्रक द्वारा विनिश्चित की जाये निवास स्थान का सहयोग करने से विवजित किया जा सकता है।

(5) जहां आर्बटिटी द्वारा परिसर के अप्राधिकृत रूप से शिकमी दिये जाने के कारण आर्बटन को रद्द करने की कार्यवाही जारी है वहां आर्बटिटी तथा उसके साथ उसमें निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को परिसर को खाली करने के लिये साठ दिन का समय दिया जायेगा। परिसर खाली किये जाने की तारीख से या आर्बटन रद्द करने के आवेदन की तारीख से, जो भी पूर्वतर हो, साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर, आर्बटन रद्द हो जायेगा।

(6) जहां निवास स्थान का आर्बटन ऐसे आचरण के कारण रद्द किया जाये जो पट्टीमियों से शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो वहां, उस अधिकारी का महानियंत्रक के विवेकानुसार उसी प्रकार का अन्य निवास स्थान प्रथम निवास स्थान से दूर किसी अन्य स्थान में आर्बटित किया जा सकता है।

(7) महानियंत्रक इन नियमों के उपनियम (1) से (5) तक के अधीन सभी कार्यवाहियां या कोई कार्यवाई करने के लिये तथा ऐसे अधिकारी को, जो नियमों का तथा उसको जारी किये गये अनुदेशों को भंग करता है, तो पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिये आवास-सुविधा के आर्बटन के लिये अपाक्षक घोषित करने के लिये भी सक्षम होगा।

23 आर्बटन के रद्द किये जाने के पश्चात् निवास-स्थान में बसे रहना--

जहां कोई आर्बटन इन नियमों के किसी उपबंध के अधीन रद्द किया जाता है या रद्द कर दिया गया समझा जाता है तो तत्पश्चात् वह निवास स्थान उस अधिकारी के जिसे वह आर्बटित किया गया हो या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के अधिभोग में बना रहता है या बना रहा हो वहां ऐसा अधिकारी उस निवास-स्थान, सेवाओं, फर्नीचर के उपयोग के लिये उतनी नुकशानी और बाग-प्रभार के संवाय का दायी होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित बाजार अनुज्ञप्ति फीस के बराबर हो या उस अनुज्ञप्ति फीस का दोगुना हो तो वह संवत् कर रहा था, इनमें से जो भी उच्चतर हो :

परन्तु किसी अधिकारी, को, विशेष दशाओं में, मू.नि. 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस से दोगुना संवाय करने पर नियम 11 के अधीन अनुज्ञान अवधि के लिये निवास-स्थान रखने के लिये महानियंत्रक द्वारा अनुज्ञान किया जा सकेगा।

24 इन नियमों के जारी किये जाने के पहले किये गये आर्बटनों का बना रहता निवास-स्थान के किसी ऐसे आर्बटन के बारे में जो इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रास्तित्व में हो यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के अधीन सम्पूर्ण रूप से किया गया आर्बटन है अथवा हो वह अधिकारी जिसे वह आर्बटन किया गया हो, नियम 5 के अधीन उस दाय्य के निवास स्थान का हकदार न हो और उस आर्बटन और उस अधिकारी के संबंध में इन नियमों के सभी वर्तमान उपबंध तत्पश्चात् लागू होंगे।

25 नियमों का निर्वहन --

यदि इन नियमों के निर्वहन की बाबत कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जायेगा।

26 नियमों का शिथिलीकरण--

सरकार ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे इन नियमों के सभी उपबंधों को या उनमें से किसी को किसी अधिकारी या निवास स्थान के मामले में या अधिकारियों के किसी वर्ग या निवास स्थानों के किसी दाय्य के बारे में शिथिल कर सकेगी।

शक्तियों या कृत्यों का प्रत्याभोजन--

महानियंत्रक इन नियमों द्वारा उसे प्रदत्त कोई शक्ति या सभी शक्तियां अपने नियंत्रणाधीन किसी अधिकारी को जिसे प्राधिकृत अधिकारी कहा जायेगा, ऐसी शर्तों के अधीन प्रत्याभोजित कर सकेगा जिन्हें अधिगोपित करना वह ठीक समझे।

[फा.सं. 39/13/92-एम-6/एम-3]

श्री राम शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 18th February, 1994

G.S.R. 137.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules regarding allotment of residence in the Indian Bureau of Mines, namely :—

1. Short title and application.—(1) These rules may be called the Indian Bureau of Mines (Allotment of Residence) Rules, 1993.

(2) They shall apply to the allotment of (and management of all) residential buildings which are under the administrative control of Indian Bureau of Mines at its Regional, Sub-regional or Headquarter offices and are meant for allotment to the officers and staff employed in those Regional, Sub-regional or Headquarter offices.

(3) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules, unless the context otherwise requires :—

(a) 'Allotment'.—means the grant of a licence to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules.

(b) 'Allotment Year'.—means the year beginning on 1st January and ending on 31st December or such other period as may be notified by the Controller General, Indian Bureau of Mines from time to time.

After the expiry of every allotment year, fresh applications are required to be called for.

(c) Controller General.—means the Head of the Indian Bureau of Mines, which is a subordinate office of Government of India under the Ministry of Mines.

(d) 'Authorised Officer'.—means an officer of the Indian Bureau of Mines authorised by the Controller General to act on his behalf in terms of these rules.

(e) 'Eligible Officer'.—means the officers and staff of Indian Bureau of Mines who are eligible for allotment of that class/type of residence which is admissible to him/her under rule 5 and is required to reside on duty at the station the residence is situated.

(f) 'Emoluments'.—means pay as defined under clause (a) of sub-rule (21) of Rule 9 of the Fundamental Rules ; (ii) for the purpose of recovery of rent means the emoluments as defined in the Fundamental rule 45(c) excluding the compensatory allowances.

EXPLANATION : In the case of an officer who is under suspension, the emoluments drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension, or if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the emoluments drawn by him immediately before that date shall be taken as emoluments.

(g) 'Family'.—means the wife or husband as the case may be and the children, step children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the officer.

(h) 'Government'.—means the Central Government.

(i) 'Priority date'.—of an officer in relation to a type of residence to which he is eligible means the earliest date from which he has been continuously drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Government or on foreign service except for a period of leave.

Provided that in respect of types A, B, C, and D residences the date from which the officer has been continuously in service under the Central Government or a State Government including the period of Foreign Services shall be his priority date for the type.

Provided further that where the priority date of two or more officers is the same, the seniority among them shall be determined by amount of emoluments, the officer in receipt of higher emoluments taking precedence over the officer in receipt of lower emoluments and where the emoluments are equal by the length of service.

(j) 'Licence fees'.—means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of Fundamental Rules in respect of a residence allotted under these rules.

(k) 'Residence'.—means any residence for the time-being under the administrative control of the Controller General and to which these rules apply.

(l) 'Sub-letting'.—includes sharing of accommodation by an allottee with another person with or without the payment of licence fee by such other person but does not include a casual guest.

EXPLANATION :—Any sharing of accommodation by an allottee with close relations shall not be deemed to be subletting.

(m) 'Temporary Transfer'.—means transfer which involves an absence for a period of not exceeding four months.

(n) 'Transfer'.—means a transfer from the existing station to any other place or from an eligible office to an ineligible office and includes a transfer or reversion to parent organisation and also deputation to a post in an ineligible office or organisation.

(o) 'Type'.—in relation to an office means the type of residence to which he is eligible under the provision of rule 5 of these rules.

3. Allotment to house owning officers.—(1) in this rule:—

(a) "adjoining municipality"—means any municipality contiguous to a local municipality.

(b) "House" in relation to an officer or member of his family means a building or part thereof used for residential purposes and situated within the jurisdiction of a local municipality or of any adjoining municipality.

EXPLANATION:—A building, part of which is used for residential purposes, shall be deemed to be a house for the purposes of this clause notwithstanding that any part of it is used for non-residential purposes.

(c) "Local Municipality" in relation to an officer means the municipality within whose jurisdiction his office is located;

(d) "Member of family" in relation to an officer means the wife or husband, as the case may be, or a dependent child of the officer.

(e) "Municipality" includes a municipal corporation, a municipal committee or boards, a town area committee, a notified area committee, and a cantonment board.

(2) An officer owning a house either in his name or in the name of any member of his family at the place of his duty or in an adjoining municipality shall be eligible for allotment of Government residence on payment of licence fee for the Government accommodation allotted to him at such rate as may be determined from time to time by the Government.

(3) When after a government residence has been allotted to an officer, he or any member of his family become owner of a house at the place of his duty or in an adjoining municipality, such officer shall notify the fact to the competent authority, i.e. Controller General/Authorised Officer within a period of one month from the date, the house is let out or occupied, on the date of completion, whichever is earlier.

4. Allotment of Residence to officers who are husband and wife—Eligibility in case of such officers:—(1) No officer shall be allotted a residence under these rules: wife or husband as the case may be, or the officer has already been allotted a residence unless such residence is surrendered.

Provided that these sub-rules shall not apply where husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any Court.

(2) Where two officers in occupation of separate residences allotted under these rules marry each other, they shall within one month of the marriage surrender one of the residences.

(3) If a residence is not surrendered as required under sub rule (2), the allotment of the residence of lower type shall be deemed to have been cancelled on expiry of such period and if the residences are of the same type, the allotment of such one of them as the Controller General may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

(4) Where both the wife and husband are employed in Indian Bureau of Mines, the title of each of them to allotment of residence under these rules shall be considered independently.

5. Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (4)—

- (a) If a wife or husband, as the case may be, who is an allottee of a residence under these rules, is subsequently allotted a residential accommodation at the same station from a pool to which these rules do not apply, she or he, as the case may be, shall surrender any one of the residences within one month of such allotment:

Provided that this clause shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

- (b) Where two officers, in occupation of separate residences at the same station, one allotted under these rules and another from a pool to which these rules do not apply, marry each other, any one of them shall surrender any one of the residences within one month of such marriage.

- (c) If a residence is not surrendered as required under clause (a) or clause (b) the allotment of the residence in the general pool shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

6. Classification of residences :—(1) For the purpose of allotment, the residences are classified as under and save as

otherwise provided by these rules, an officer shall be eligible for allotment of a residence of the type shown in the table below:—

Type of Residence	Monthly emoluments as on the first day of the allotment year in which the allotment is made
Type-I	Less than Rs. 950/- per month.
Type-II	Less than Rs. 1500/- per month but not less than Rs. 950/- per month.
Type-III	Less than Rs. 2800/- per month but not less than Rs. 1500/- per month.
Type-IV	Less than Rs. 3600/- per month but not less than Rs. 2800/- per month.
Type-V	Less than Rs. 5900/- per month but not less than Rs. 3600/- per month.
Type-VI	Less than Rs. 7300/- per month but not less than Rs. 5900/- per month.
Type-VII	Less than Rs. 8000/- per month but not less than Rs. 7300/- per month.

(2) An officer eligible to Type V and above shall also be eligible to the next below type of residence.

7. Application for Allotment & Determination of seniority:—Every officer, who desires to have an allotment made under these rules, shall submit within one month of reporting for duty at the office concerned, an application in Form 'A' provided in the Annexure to these rules, to the Controller General or any officer authorised on his behalf.

The seniority of eligible officer who are holding a permanent or temporary post, for the purpose of allotment of residence, shall be determined by the date of reaching the qualifying limit of pay prescribed for each class of residence under these rules.

Provided that if two or more officers of same seniority are eligible, the seniority among them shall be determined by the amount of emoluments; higher emoluments taking precedence over the emoluments next below or where the emoluments are equal, by the period or for which these emoluments have been drawn in the post held by such officer at the time of application the longer period taking precedence over the period next below. When the seniority and emoluments are same, the allotment will be made to the officer who is older in age.

8. Allotment of residence :—(1) Save, as otherwise provided in these rules a residence on falling vacant will be allotted by the Controller General, Indian Bureau of Mines preferably to an applicant desiring a change of accommodation in that type and if not required for that purpose, to an applicant without accommodation in that type having the earliest priority date for such type of residence subject to the following conditions:

- (i) The residence of a type higher than that to what the applicant is eligible will not normally be allotted except when the accommodation of the type to which he is eligible is not available.

The applicant shall not be compelled to accept the residence of a lower type than to which he is eligible and if the entitled type is not available then lower type can be allotted, subject to the condition

that the applicant will have to vacate the lower type when the entitled type is available for allotment and it is allotted to him.

- (ii) On a request from an applicant for allotment of a lower category residence, a residence next below type for which the applicant is eligible under rule 5 may be allotted to the applicant on the basis of his priority date for the same.

Provided that the Controller General may cancel the existing allotment of an officer and allot him an alternative residence of same type or in an emergency circumstances, an alternative residence of the type of residence in occupation of the officer if the residence in occupation of the officer is required to be vacated for Government work

(2) The holder of a temporary post to whom a residence is allotted shall revert to a lower class of residence as soon as one can be made available for him, if he is at any time reverted to a lower post not entitling him to the class of accommodation allotted and this shall be an express condition of the allotment.

- (a) In the Lady Officers' Pool, on the basis of the priority date on which each such officer became eligible for the type of residence in that pool.

10. Out-of-turn allotment :

Notwithstanding anything contained in the provisions of rule 7, the allotment of residence may be made by the Controller General on out of turn basis to an officer on the ground of serious illness of self or a member of his family suffering from PUL. T.B /Cancer, Heart and Physically handicapped etc. (as per statement appended below) in consultation with the prescribed medical authority. In such cases, allotment may be made according to the actual date of receipt of the out of turn application, subject to availability of entitled type of quarters. In case, entitled type of quarter is not readily available, consideration for allotment of next below type if immediately available shall also be made

Name of diseases	Entitlement	Medical Certificate/Competent Authority
1	2	3
Heart Ailment	Government servant (self only)	Certificate having symptoms of Gr. III & IV issued by Heart Specialists/ Cardiologist duly countersigned by the Medical Superintendent of the concerned hospital.
Cancer	Illness of government servant himself and his family i.e. wife/husband and the children.	Cancer Malignant non-plasim in active phase duly countersigned by the M.S. of the concerned Hospital.
Pul. T.B.	-do-	Pulmonary tuberculosis (in active phase with risk to others and sputum positive) duly countersigned by the M.S. of the concerned Hospital.
Physically Handicapped	Government servant (self only)	Physically handicapped to the extent of 40% (disability) Medical Certificate from the Medical Board of the Hospital concerned and countersigned by the Medical Superintendent.

9 Maintenance of separate pools for certain categories of officers —(1) Notwithstanding anything contained in these rules, following pool shall be maintained, namely :

- (i) "Lady officers" Pool—separately for married lady officers and for single lady officers

Explanation —

- (a) "Married Lady Officer" means a lady officer whose marriage is subsisting and who is not judicially separated from her husband

- (b) "Single Lady Officer" means a lady officer who is not a married lady officer.

(2) The number and type of residences to be placed in this pool shall be determined by the Department from time to time.

(3) The Officers shall be entitled to allotment of accommodation in the said pool in the type next below the type to which they are entitled under the provisions of rule 5.

(4) The inter-se-seniority of the officer eligible for the allotment of residences under this rule shall be determined in the following manner, namely

1	2	3
Blind (categories for physically handicapped)	Government servant (self only)	The blind i.e. those who suffer from either of the following conditions : (a) Total absence of sight; (b) Visual Acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snellon) in the better eye with correcting lenses; (c) Limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degrees or worse.
Deaf (categories for physically handicapped)	-do-	The deaf are those in whom the cause of hearing is non-functional for ordinary purposes of life.

10. Non-acceptance of allotment of offer or failure to occupy allotted residence after acceptance—Drawal of house rent allowance :

- (1) If any officer fails to accept allotment of government residence, he shall not be eligible for further allotment for one year and shall be entitled to draw house rent allowance only in terms of rule 10(3).
- (2) If an officer occupying a lower type of residence is allotted a residence of the type for which he is eligible under rule 5, he may on refusal of such allotment or offer of allotment be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions :—
 - (a) Such an officer shall not be eligible for another allotment for a period of six months from the date of allotment order for the higher class of accommodation;
 - (b) While retaining the existing residence he shall be charged the same licence fee which he would have had to pay under Fundamental Rules 45(a) in respect of the residence so allotted or offered or the licence fee payable in respect of the residence already in his possession whichever is higher.
- (3) On the basis of applications received if Authorised Officer is not in a position to allot the entitled type of accommodation, he shall issue 'No Accommodation Certificate' on behalf of the Controller General, Indian Bureau of Mines. On such production of 'No Accommodation Certificate' by the employee, the House Rent Allowance shall be payable to the employee with effect from the date of 'No Accommodation Certificate'.

11. Miscellaneous :

The Controller General may also make allotment of quarters to any of the Central Government Department officers and staff in case such an application is received subject to the condition that there is no applicant from Indian Bureau of Mines for allotment and such of those people will have to pay licence fee, water and electricity charges and they will be governed by allotment of residence rules of Indian Bureau of Mines. Such allotment may be made when the supply is more and demand is less from Indian Bureau of Mines side and such an allottee will be governed by allotment rules of Indian Bureau of Mines.

12. Period for which allotment subsists and the concessional charge for further retention :

- (1) The allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the officer and shall continue in force until :
 - (a) The expiry of concessional period permissible under sub-rule (2) after the officer ceases to be on duty at that particular station, or
 - (b) It is cancelled by the Controller General or is deemed to have been cancelled under provision under these rules, or
 - (c) It is surrendered by the officer, or
 - (d) The officer ceases to occupy the residence.
- (2) The residence allotted to an officer may, subject to sub-rule 3, be retained on the happening of any of the things specified in column 1 of the table given below for a period specified in the corresponding

entry in column 2 thereof, provided that the residence is required for a bona fide use of the officer or member of his family :

Events	Permissible period for retention of the residence
(i) Resignation, dismissal, removal or termination of service	1 month
(ii) Retirement or terminal leave	4 months
(iii) Death of the allottee	6 months
(iv) Transfer to a place outside the station of allotment of residence	2 months
(v) On proceeding on foreign service in India	2 months
(vi) Temporary transfer in India or transfer to a place outside India	4 months
(vii) Leave (other than leave preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave or study leave)	For the period of leave but not exceeding four months.
(viii) Leave preparatory to retirement or refused leave granted under Fundamental Rule 86	For the full period of leave on full average pay subject to maximum of 4 months inclusive of the period permissible in the case of retirement.
(ix) Deputation outside India	For the period of deputation but not exceeding 6 months except on payment of market rent.
(x) Leave on medical grounds (other than R.B. leave)	For the period of leave but not exceeding 8 months.
(xi) Medical leave on grounds of T.B. or Cancer or such other serious illness.	For the full period of leave.
(xii) On proceeding on training or study leave	For the full period of training or study.

Explanation :

- (1) The period permissible on transfer mentioned against items (iv), (v), (vi) and (ix) shall count from the date of relinquishing charge plus the period of leave, if any, sanctioned to and availed of by the officer before joining duty at the new office.
- (2) Where a residence is retained under sub-rule 2, the allotment shall be deemed to be cancelled on expiry of the admissible concessional period unless immediately on the expiry thereof, the officer resumes duty at a place where a residence had been allotted to him.
- (3) Where an officer is on medical leave without pay and allowances, he may retain his residence by virtue of the concession under items (x) and (xi) of the Table below sub-rule (2), provided he remits the licence fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such licence fee for more than two months, the allotment shall stand cancelled.

13. Provision relating to licence fee:—(1) On allotment of an accommodation, licence fee and service charges shall be charged under rule 45 of Fundamental Rules and shall be deducted from pay bills of the officer. The liability for licence fee shall commence from the date of occupation or the 8th day from the date of receipt of allotment order whichever is earlier.

(2) An officer who fails to take possession of the residence that is allotted to him within 8 days from the date of receipt of allotment letter shall be charged licence fee from such date upto a period of one month or upto the re-allotment of that particular accommodation whichever is earlier.

(3) Where an officer in occupation of a residence, is allotted another residence and occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence. He may, however, retain the former residence without payment of licence fee for that day and the subsequent day for shifting.

14. Personal liability of the officer for payment of licence fees and furnishing of surety bond of temporary Government Servants:—(1) An officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for payment of licence fee thereof and for any damage beyond fair, wear and tear caused thereto or to the furnitures, fixtures or fittings and

services provided therein during the period for which the residence has been allotted and remain allotted to him or where the allotment has been cancelled under any of the provisions of these rules, until the residence has been vacated and full vacant possession thereof has been restored to the Government.

(2) Where an officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government servant, he shall execute a security bond in the form prescribed for in this behalf by the Government with a surety who shall be a permanent Government servant of equal or higher status and serving under the Central Government for due payment of all rent and other charges payable by him in respect of such a residence.

(3) If the surety ceases to be in Government service or becomes insolvent or withdraws his guarantee or ceases to be ineligible for any other reasons the officer shall furnish a fresh surety within 30 days from the date of his cancellation of the surety bond and if he fails to do so the allotment of the residence to him shall be deemed to have been cancelled with effect from the date of that event.

(4) Water and electricity charges shall be paid by the allottee to the concerned authorities as per the meter reading and the rates specified by those authorities. Where common meter is provided the Controller General in consultation with CPWD or State PWD will fix the flat rate and the allottees will pay according to that rate.

15. Surrender of allotment and period of notice:—(1) No officer shall surrender the Government accommodation allotted to him under these rules unless specifically permitted by the Controller General or any officer authorised on his behalf, to do so subject to the fulfilment of conditions laid down under sub-rule (2) of rule 11 or in the event of his transfer to outstation office.

(2) When he is permitted to surrender an allotment—

- (a) he shall not retain any right on the particular residence allotted to him;
- (b) he shall give a notice of his intention of surrendering the residence atleast 10 days before the date of vacation of the residence. If he fails to do so, rent for 10 days or for the period for which it falls short of 10 days shall be charged.
- (c) he shall not draw any House Rent Allowance unless specifically sanctioned by Controller General or any authorised officer on his behalf.

16. Change of Residence:—(1) An officer to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same type not more than one change shall be allowed in respect of one type of residence allotted to the officer.

(2) Changes shall be offered in the order of applications for the same received in the office of Controller General.

(3) If an officer fails to accept the change of residence offered to him, within five days of the issue of offer of allotment, he shall not be considered again for a change of residence to that type for one year

(4) An officer who after accepting a change of residence fails to take possession of the same, shall be charged licence fee for such residence in accordance with the provisions of sub-rule (1) of Rule 12 in addition to the normal licence fee under rule 45 of Fundamental Rules for the residence already in possession, the allotment of which shall continue to subsist.

17. Change of Residence in the event of death of family member:—Notwithstanding anything contained in rule 15 an officer may be allowed a change of residence on the death of

any member of his family if he applied for a change within 3 months of such occurrence provided that the change will be given in the same type of residence as the residence already allotted to the officer.

18. Mutual Exchange of Residence:—The officers to whom the residence of the same type have been allotted on the same station under these rules may apply for permission to the Controller General for mutual exchange and may be granted if both the officers are reasonably expected to be on duty in the same station and are interested in their mutual exchange of residence for atleast 6 months from the date of approval of such exchange.

19. Transfer to non-family stations:—If an officer is transferred on deputation to a station where he is not permitted or advised by the Government to take his family with him and the residence allotted to him under these rules is required by the family for staying at the station, the officer may be allowed on request to retain the residence in payment of licence fee under rule 45-A of the Fundamental Rules till the permanent transfer of the officer to a station where he is permitted by the Government to take his family with him.

20. Responsibility for Maintenance of Residence:—(1) An officer to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and the premises in a clean condition to the satisfaction of the Controller General or an officer authorised by him on his behalf.

(2) The officer to whom a residence has been allotted shall not grow any tree, in the premises or cut down or loop off any existing trees without the permission of the Controller General.

(3) An officer to whom a residence has been allotted shall be required when he enters into the occupation of residence, to sign an inventory of furniture any fittings etc. that are provided in the residence and also of trees planted.

21. Subletting or sharing of Residence:—(1) No officer shall share the residence allotted to him or any of the out-houses, garages and apartments etc. thereto except with the employees of Indian Bureau of Mines. The servant quarters, outhouses, garages etc. may be used only for the bona fide purpose including the residence of allottee, or for such other purpose as may be permitted by the Controller General.

(2) No officer shall sub-let whole of his residence provided that the officer proceeding on leave may accommodate, in the residence any other officer eligible to share government residence as a caretaker for a period not exceeding six months.

(3) Any officer who shares or sublets his residence shall do so at his own risk and responsibilities and shall remain personally responsible for any licence fee payable in respect of residence and for any damage caused to the residence or its precincts or grounds or services provided therein by the Government, beyond fair, wear and tear.

(4) Sharing of residence may be allowed only with the prior permission of the Controller General.

22. Consequences of breach of Rules and Conditions:—(1) If an officer to whom a residence has been allotted sublets the residence on charging rent from the sharer at a rate which the Controller General considers excessive, erects or constructs any unauthorised structure in any part of the residence or house, uses the residence or any portion thereof for any purpose other than that for which it is meant, or tampers with the electric or water connections or commits any other breach of rules or terms and conditions of the allotment, or uses the residence or premises and conducts himself in a manner which in the opinion of the Controller General is prejudicial to the maintenance of the harmonious relations with his neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement, with a view to acquire the allotment, the Controller General may

without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence.

(2) If the officer has failed to notify to the Controller General as provided under rules 4(2), 20(4) or while so notifying any application or statement suppresses any material fact, Controller General may cancel the allotment with effect from the date he became ineligible for allotment of Government accommodation under the said rules.

(3) If an officer sublets the residence allotted to him or any portion thereof or any outhouses, garages, stables, appurtenant in contravention of these rules, he shall without prejudice to any other action that may be taken against him be charged licence fee at four times the standard licence fee under rule 45-A of Fundamental Rules.

(4) The quantum of licence fee to be recovered in each case will be decided by the Controller General on merit. In addition, the officer may be debarred from the sharing of the residence for a specified period in future as may be decided by the Controller General.

(5) Where action to cancel the allotment is taken on account of unauthorised subletting of the premises by the allottee, a period of sixty days shall be allowed to the allottee, and any other person residing with him therein to vacate the premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the orders for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.

(6) Where the allotment of residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with the neighbour, the officer, at the discretion of the Controller General may be allotted another residence in the same class at a place away from the first residence.

(7) The Controller General shall be competent to take all or any of the action under sub-rule 1 to 5 of this rule and also to declare the officer who commits a breach of the rules and instructions issued to him, to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding 5 years.

23. Overstayal in residence after cancellation of allotment :—Where, after an allotment has been cancelled or deemed to be cancelled under any provisions contained in these rules, the residence remain or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or of any person claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of residence, services, furniture and garden charges equal to market licence fee as may be determined by the Government from time to time or twice the licence fee he has paying, whichever is higher :

— Provided that an officer, in special cases may be allowed by the Controller General to retain the residence on payment of twice the standard licence fee under rule 45-A of Fundamental Rules for a period permitted under rule 11.

24. Continuance of allotment made prior to the issue of these rules : Any allotment of a residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the officer to whom it has been made is not entitled to a residence of the type under rule 5 and all present provision of these rules shall apply in relation to that allotment and that officer accordingly.

25. Interpretation of rules : If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government.

26. Relaxation of rules : The Government may for reasons to be recorded in writing relax any or all of the provisions of these rules in the case of any officer or residence or class of officers or type of residences.

27. Delegation of power of functions : The Controller General may delegate any or all the powers conferred upon him by these rules to any officer to be called authorised officer under his control subject to such conditions as he may deem fit to impose.

[F. No. 39/13/92-M.VI./M.III]

SIRI RAM SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1994

सा.का.नि. 138 :—राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ज्ञान मंत्रालय में निदेशक (तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ज्ञान मंत्रालय (समूह 'क' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो उक्त उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य शर्तें :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शर्तें और उसमें संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अन्वीन अंग्रेज है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—यहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें देखकर नया संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संधि में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वर्तमान	न्यूनतम पद अथवा अधिकतम पद	साथे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जाने गए वर्षों की पापदा केन्द्रीय निविदा सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुसूचित है या नहीं।
1	3	3	4	5	6	7
निदेशक (तकनीकी)	1* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित (अनुसूचित)	4500-150-5700 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	साथे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं शैक्षिक और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत स्थितियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिशीला की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : सभी सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
---	---

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूविज्ञान क्षेत्र के ऐसे अधिकारी :- (क) जो नियमित आधार पर सक्षम या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं, या (ख) जिन्होंने 3700-125-4700-150-5000 रु. या समतुल्य वर्तमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उमी या किसी अन्य संगठन/विभाग के इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य नाइबरबाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी) (प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति गमिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में यह लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
---	---

13	14
लागू नहीं होता	यह लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.स. 3 (25)/90-स्था.पट्टे]
अनुसूचित मिश्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd February, 1994

G.S.R. 138.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Technical) in the Ministry of Mines, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Mines (Group 'A' Technical posts) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of post(s), its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications : No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification
(1)	(2)	(3)
Director (Technical)	1* (1993) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted (Non-ministerial)

Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruit
(4)	(5)	(6)
Rs. 4500-150-5700	Not applicable	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation

In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotional Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making rectt.
---	--	--

(12)	(13)	(14)
Officers of Geological Survey of India in the Geology Stream	Not applicable	Consultation with UPSC not necessary
(a) holding analogous post on regular basis, or equivalent;		
OR		
(b) with 5 years regular service in a post in the pay-scale of Rs. 3700-125-4700-150-5000 or equivalent.		
(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.)		
(The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall not exceed 56 years as on the last date of receipt of applications).		

[F.No. 3(25)/90/Estt.. (Pt.)]
ANURAG MISRA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1994

सा. का. नि. 139 राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि और सहकारिता विभाग सहायक निदेशक (खाद) भर्ती नियम, 1960 को, उन बातों के सिवाय अधीकृत करने हुए, जिन्हें ऐसे अधीकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) में सहायक निदेशक (खाद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्--

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और सहकारिता विभाग, सहायक निदेशक (खाद) भर्ती नियम, 1960, है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान-- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता-- वह व्यक्ति--
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्थायी विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने का शक्ति-- जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या सगीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यापृति:—इन नियमों की कोई बात ऐसे प्रारक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए प्रावेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना प्रपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशान) नियम 1972 नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------	---------------------	---	--

1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक (आव)	1* (1990) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	2200-75-2800-द. रो.-100-4000 रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	हां
					टिप्पणियाँ:—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत से अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेवालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अरुणाचल और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए बहिष्कृत की गई है)।	

सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य
ग्रहणाएँ

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
विहित आयु और शैक्षिक ग्रहणाएँ प्रोन्नत
व्यक्तियों को दशा में लागू होंगे या नहीं

परिबीजा की अवधि यदि कोई हो

8

9

10

आवश्यक:-

(1) किन्ना मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान,
जैव रसायन विज्ञान, कृषि रसायन, सूक्ष्मशैक्षिक, सामा-
जिक विज्ञान या कृषि में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

आयु: नहीं

शैक्षिक ग्रहणाएँ : नहीं

परन्तु उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्व-
विद्यालय से कृषि में डिग्री या समतुल्य हो।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए

1 वर्ष प्रोन्नति अधिकारियों के लिए

2 वर्ष।

(2) गृहरो और प्राचीन अपविष्ट सामग्री से बड़े पैमाने पर
कमोस्ट उत्पादन कार्य का 3 वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी:- 1. ग्रहणाएँ अन्यथा सुग्राह्य अभ्यर्थियों की दशा में
मध्य लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल
की जा सकती है।

टिप्पणी:- 2. अनुभव संबंधी अर्हता (ग्रहणाएँ) मध्य लोक सेवा
आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में
नव शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन
के किसी प्रक्रम पर मध्य लोक सेवा आयोग की
यह राय है कि उनके लिए आरक्षण रिक्तियों
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले
उन मनुष्यों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती को पद्धति, भर्ती मोचे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रभावसत्ता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।

11

12

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके
अंतर्गत अल्पकालिक मविदा भी है) द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी
भर्ती द्वारा।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण:- (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक मविदा भी है)।

1. केन्द्रीय सरकार (राज्य सरकारों) भारतीय कृषि अनुसंधान (लोक उप-
क्रांति/ग्रहण सरकारी स्वायत्त या कानूनों सगठनों के अधीन ऐसे अधिकारों

(क) (i) जो नियमित आधार पर सर्वश्रेष्ठ पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने 2000-3500 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों
पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने 1640-1900 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों
पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिसके पास कमसे कम 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों
के लिए अधिकृत शैक्षिक ग्रहणाएँ और अनुभव हो। सम्प्रेषक (फोर्डर)
श्रेणी के ये विभागीय अधिकारों जो प्रोन्नति को सीधी लाईन
में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र नहीं
होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए
विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। केन्द्रीय सरकार के उम्मीदवारों किसे
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य
कार्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति का अवधि सहित प्रतिनियुक्ति का
अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

प्रोन्नति:-

1. ऐसा सहायक विकास अधिकारी (खाब) (2000-3500 रुपए)

2. ऐसा तकनीकी अधिकारी (कम्पोस्ट और मल) (2000-3500 रुपए)

(जिसने संबंधित श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सब लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

13

14

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. अध्यक्ष, सबस्य, सब लोक सेवा आयोग | अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) | सदस्य |
| 3. संयुक्त सचिव (उर्बरक) | सदस्य |
| 4. निवेष्टक (कामिक) | सदस्य |

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए)

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) | अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव (उर्बरक) | सदस्य |
| 3. निवेष्टक (कामिक) | सदस्य |
| 4. संयुक्त आयुक्त (उर्बरक) | सदस्य |

टिप्पणी-- सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ, सब लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति को बैठक सब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

[सं. 12018/1/84- - स्पा.-I]

एन. के. मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 11th February, 1994

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Agriculture and Cooperation, Assistant Director (Manures) Recruitment Rules, 1960 & 1990 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Manures) in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, namely:—

1. Short title and commencement :

- (i) These rules may be called the Department of Agriculture and Cooperation, Assistant Director (Manures) Recruitment Rules, 1990.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay:—

The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc:—

The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications : No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax : Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving : Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification
1	2	3
Assistant Director (Manures)	1* (1990) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service Group 'A' Gazetted.
Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
4	5	6
2200-75-2800 E.B.- 100-4000	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India) and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
--	---

7

8

Yes

ESSENTIAL:

- (i) Master's Degree in Chemistry, Bio-Chemistry, Agricultural Chemistry, Microbiology, Social Agriculture of a recognised University or equivalent.
- (ii) 3 years experience of a Compost production work on a large scale from Urban and Rural Waste materials.

NOTE :

1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.
2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
---	-----------------------------

9

10

Age : No. Educational Qualifications: No, but must possess a degree in Agriculture from a recognised University or equivalent.	1 year for direct recruits and 2 years for promotee officers.
---	--

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods

11

By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract), failing both by direct recruitment.
--

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.

12

PROMOTION:

1. Assistant Development Officer (Manure) (Rs. 2000-3500).
2. Technical Officer (Compost and Sewage) (Rs. 2000-3500).
with three years regular service in the respective grade.

TRANSFER ON DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT) :

1. Officers under the Central/State Governments/Indian Council of Agricultural Research/Public/Undertaking, Semi-Government, Autonomous or Statutory Organisations:—

- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or
- (ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; or
- (iii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 and

(b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Column 8.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion)

1. Chairman/Member, UPSC—Chairman
2. Joint Secretary (Administration)—Member
3. Joint Secretary (Fertiliser) - Member
4. Director (Personnel)—Member

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation)

1. Joint Secretary (Administration)—Chairman
2. Joint Secretary (Fertiliser) —Member
3. Director (Personnel)—Member
4. Joint Commissioner (Fertiliser)—Member

NOTE : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[No. 12018/1/84-Estt. 1]

S.K. MISHRA, Under Secy.

जल ससाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

सकल्प

RESOLUTION

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1994

New Delhi, the 4th February, 1994

सा का नि. 140--इस मंत्रालय के दिनांक 3 जनवरी, 1991, 11 मार्च, 1991, 25 मार्च, 1992, और 25 मई, 1992 के संकल्प संख्या 14/1/89-हिन्दी तथा दिनांक 4 अगस्त, 1992, 16 सितम्बर, 1992 29 अक्टूबर, 1992 तथा 29 जुलाई, 1993 के संकल्प संख्या 14/1/92-हिन्दी के अनुक्रम में भारत सरकार ने जल ससाधन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 28 मई, 1995 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

G.S.R. 140.—In continuation of this Ministry's Resultant No. 14/1/89-Hindi dated 3-1-1991, 11-3-91, 25-3-92, and 25-5-92 and Resolution No. 14/1/92-Hindi dated 4-8-92, 16-9-92, 29-10-92, and 29-7-1993 the Government of India has decided to extend the Tenure of Hindi Salahkar Samiti of Ministry of Water Resources upto 28th May, 1995.

आदेश

ORDER

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों को भेज दी जाये।

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all the members of the Samiti, All State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of Government of India.

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जनसामान्य के सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

[संख्या 14/6/93-हिन्दी]

[No. 14/6/93-Hindi]

अभय प्रकाश, संयुक्त सचिव

ABHAY PRAKASH, Jt. Secy.